भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1946

जिसका उत्तर 5 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

14 अग्रहायण, 1941 (शक)

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

1946. श्री अश्वनी वैष्णव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए अलग से विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना शुरू करने की आवश्यकता के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम ने विदेशी छात्रों को भी आकर्षित किया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और **(ख)** : ''राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एनपीई-2012)'' और ''राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति (एनपीआईटी-2012)'' में आरएण्डडी, नवोद्भव और आईपी सृजन पर जोर दिया गया है। एनपीआईटी 2012 में यह सुझाव दिय गया है कि आईटी/आईटीईएस उद्योग/'सेवा आधारित' मॉडल से एक 'उत्पाद आधारित वृद्धि मॉडल की ओर बढ़े, अत: इस क्षेत्र में देश में पीएचडी धारकों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया गया कि आईटी/आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन के क्षेत्र में 25 % कर्मचारी पीएचडी स्तर के होने चाहिए। ऐसा इकोसिस्टम सृजित करने के लिए इन क्षेत्रों में पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2014 में '' इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी समर्थित सेवा (आईटी/आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ''योजना अनुमोदित की, जिसे अब '' इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वश्वरैया पीएचडी योजना'' के तौर पर जाना जाता है। नामांकित 934 पूर्ण कालिक पीएचडी उम्मीदवारों में से दो विदेशी विद्यार्थी हैं।

******